Reported Harassment of IAS/IPS officers

*97. DR. RATNAKAR PANDEY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a newspapers report which appeared in the *Hindustan Times* of January 12, 1989 to the effect that the All India Services Officers Association has accused the Telugu Dasam Government of Andhra Pradesh for systematically harassing the IAS/IPS officers there;

(b) whether the Central Government have received a copy of the memorandum in this regard; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes, Sir.

(b) No memorandum was received recently, or in the context of the news item. However, a memorandum was received in 1987. Besides, a copy of the minutes of the meeting of the executive committee of the IAS Officers Association, Andhra Pradesh Branch held on 28th November, 1988 was received in January, 1989.

(c) The memorandum referred to selective victimisation of officers through raids, suspension etc., on false flimsy and frivilous grounds. The executive committee in its meeting sought broad parity in promotion in All India Services, at higher levels and posting of officers of certain levels of seniority only to posts of suitable levels depending upon the status, level and responsibility of the post. The committee urged that investigating agencies be advised not to give premature and adverse publicity against officers.

देश के विभिन्न भागों में हुए विकास में अंतर

*98. **श्री राम जेठमलानी :**

सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों के विकास में भारी अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि देश में विकास के इस अंतर को दूर करने के लिए 1985 के वर्ष में आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में एक फार्मूले पर अमल करने का निर्णय किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस फार्मूले का ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस फार्मूले के अधीन किन-किन पिछड़े क्षेत्रों में क्या-क्या योजनाएं क्रियान्वित की गईं; और

(ङ) इन योजनाओं के परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों को क्या-क्या लाभ प्राप्त हुए ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी हां, देश के विभिन्न भागों में विकास में अन्तर है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय विकास परिषद की 1985 में हुई बैठक के समय यह स्पष्टीकरण दिया गया था कि आयोग ने गाडगिल फार्मूले के संशोधन, बाजार-ऋण की आबंटन पद्धति में परिवर्तनों और पूर्वी भारत तथा भूखी भूमि क्षेत्रों में उच्चतर कृषीय संवृद्धि पर बल देने, जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से प्रादेशिक विषमताओं को खत्म करने का हमेशा प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त पिछड़े क्षेत्रों/लोगों जैसे पर्वतीय क्षेत्रों, द्वीपसमूह विकास, जनजातियों, गरीबों इत्यादि में सुधार करने के लक्षित कार्यक्रमों को और मजबूत किया गया